

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-1 05/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी रुद्रपुर ऊधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी रुद्रपुर ऊधम संह नगर के माह 04/2016 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.11.17 से 18.11.17 तक श्री नवीन चन्द्र लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 01.03.2017 तक श्री हिमांशू मण लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह – से – तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: – जिला खान अ धकारी रुद्रपुर ऊधम संह नगर
3. (ii)(अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2014-15	1983.00
2015-16	2540.93
2016-17	3434.75

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
			लागू नहीं					

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है: (संलग्न है)

निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओं का संग्रह किया गया।

राजस्व: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

प्रस्तर1- ब्याज का आरोपण 4.35 लाख।

प्रस्तर2- अर्थदण्ड का न्यूनारोपण 1.75 लाख।

प्रस्तर3- अर्थदण्ड 1.40 लाख।

प्रस्तर4- आवेदन शुल्क कम जमा लिखा जाना 0.95।

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग 2 ख

प्रस्तर- 1 : अपरिहार्य वार्षिक भाटक/रॉयल्टी व अन्य देय शुल्क वलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का अनारोपण रु 4.35 लाख ।

उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) वभाग की वज्रप्ति दिनांक 26.08.2001 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-58(1) के अनुसार राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निम्न प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामत्व (रॉयल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराश या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे । नियम 58(2) के अनुसार उपनियम (1) के अधीन सूचना की अवधि के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय कसी भाटक, स्वामत्व, सीमांकन शुल्क और कन्ही अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग (2) के कार्यालय ज्ञाप सं. 2911/VII-II/146-ख/10/2011 देहरादून, दिनांक 18.11.2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 के बिन्दु 5(5) के अनुसार समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञा पत्रधारक/भंडारण स्वामी को निर्गत कये जाने वाले परिवहन प्रपत्रों पर खनिज की मात्रा का निर्धारण कर रॉयल्टी की धनराश अग्रम रूप से जमा करायी जायेगी । पुनः उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास वभाग के कार्यालय ज्ञाप सं. 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनांक 31-07-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं. 9(4) (पाँच) के अनुसार खनन संक्रयाएँ प्रारम्भ करने के पश्चात पट्टेधारक द्वारा आगामी माह की 20 तारीख तक रॉयल्टी की अग्रम राश जमा की जाएगी। निर्धारित तिथि तक अग्रम जमाने कए जाने की दशा में खान अधिकारी द्वारा 10 दिन के भीतर वलम्ब शुल्क 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा कये जाने का नोटिस जारी कया जायेगा।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में निजी पट्टाधारकों की पत्रावलियों की जाँच में संलग्न ववरण अनुसार 01 पट्टाधारक द्वारा अपनी वार्षिक भाटक/रॉयल्टी की धनराश वलम्ब से जमा करायी गयी थी, जिसपर नियमानुसार रु 290463/- ब्याज देय था ।

आगे जाँच में यह भी पाया गया क पट्टाधारक द्वारा वर्ष 2016-17 के माह मार्च 2017 में 30373.75 टन उप-खनिज की निकासी की रॉयल्टी रु 24,29,900/- पर देय रिवर ट्रेनिंग

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-105/2017-18

शुल्क, वकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति शुल्क रु 9,96,259/- वलम्ब (07 माह 08 दिन) से दिनांक 08.11.2017 को जमा कराया गया था जिसपर नियमानुसार 24% की दर से रु 144789/- ब्याज भी देय था जो क पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा गया क संबन्धित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ब्याज की राश `290463 + `144789 (कुल `435252/-) जमा न कराये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 2 : अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण रु 1.75 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. 1031/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनांक 31.07.2015 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 में संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी थी । इस नियमावली के बिन्दु सं. 11 द्वारा नियम 13 के उप-नियम-2 के खण्ड (ख) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया था:

अवैध भंडारकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/ अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं वनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम (2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराश रु 2,00,000/- के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा का वक्रय मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना तक) की धनराश उपरोक्तनुसार आंगणत कर वसूली की जायेगी ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अवैध खनन से संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया क उप-जिला अधिकारी, सतारगंज द्वारा अवैध उप-खनिज के भंडारण के सम्बंध में दिनांक 21.08.2015 को जिला अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.08.2015 को उप-जिला अधिकारी, सतारगंज द्वारा निरीक्षण के दौरान ग्राम कल्याणपुर, सतारगंज में उपखनिज मात्रा 280 घनमीटर का अवैध भंडारण पाया गया था। इस सम्बंध में राजस्व निरीक्षक व उप-जिला अधिकारी, सतारगंज द्वारा अवैध भंडारण किये जाने हेतु रॉयल्टी की धनराश के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में मात्र रु 25000/- आरोपित किये जाने हेतु आख्या जिला अधिकारी को प्रेषित की गयी थी। उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रॉयल्टी की धनराश के अतिरिक्त रु 25000/- का अर्थदण्ड वपक्षी पर आरोपित किया था जब क नियमानुसार रु 200000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था। इस प्रकार अवैध खनन के प्रकरण में रु 175000/- अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क संबन्धित प्रकरण में जिला अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया गया है एवं कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /DMO-105/2017-18

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यूं क नियमानुसार अर्थदण्ड का आरोपण नहीं कया गया था। अतः रु 175000/- के अर्थदण्ड के न्यूनारोपण का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

मा सक ववर णयाँ प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण रु 1.40 लाख।

उत्तराखंड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-73 के अनुसार खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बंध में ववरणी अनुवर्ती माह के द्वतीय सप्ताह में प्रपत्र एम. एम.-12 में जिला अ धकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा । पुनः उत्तराखंड, औद्ध्यो गक वकास वभाग के कार्यालय जाप सं. 1033XII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून, दिनांक 31-07-2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईट आदि) नीति, 2015 के बिन्दु सं. 6(6) के द्वारा त्रैमा सक ववरणी के स्थान पर मा सक ववरणी का प्रावधान करते हुए ववरणी समय से प्रस्तुत न करने की दशा में अर्थदण्ड की धनरा श को रु 400 से बढ़ाकर रु 2000 कर दिया गया था ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अ धकारी/उप-निदेशक, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क 10 उप-खनिज भण्डारकर्ताओं द्वारा अपनी मा सक ववरणी या तो वलम्ब से जमा की गयी थी या जमा ही नहीं की गयी थी। अतः उपरोक्त वर्णत नियमानुसार 10 उप-खनिज भण्डारकर्ताओं (संलग्न सूची अनुसार) द्वारा अपनी 70 मा सक ववर णयाँ वलम्ब से प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने के कारण रु 2000 प्रति मा सक ववरणी की दर से रु 1,40,000/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क आरो पत नहीं कया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क ववरणी वलम्ब से प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत न करने के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर- 3 : आवेदन शुल्क की धनराश कम जमा कया जाना रु 0.95 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्ध्योगिक विकास वभाग, कार्यालय ज्ञाप सं. 1033/MII-1/2015/146-ख/2010 दिनांक 31.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 के नियम 4(3) के अनुसार स्वस्थित चट्टानों/मदी तल से संबन्धित निजी नाप भूम में खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क रु 1.00 लाख लये जाने का प्रावधान था ।

कार्यालय जिला ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप-निदेशक, खनन, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में खनन पट्टों से संबन्धित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि श्री आशीष सहगल पुत्र श्री ओमकार सहगल, निवासी ए-441, आवास विकास, कछा, ऊधम सिंह नगर के पक्ष में ग्राम सरोली कलाँ में 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत कया गया था जिसका पट्टा वलेख दिनांक 31.05.2016 को निष्पादित कया गया था । नियमानुसार खनन पट्टे हेतु आवेदन शुल्क रु 1.00 लाख था जबकि पट्टाधारक द्वारा दिनांक 04.02.2014 को आवेदन शुल्क के रूप में मात्र रु 5000/- ही जमा कराया गया था । इस प्रकार रु 95000/- आवेदन शुल्क कम जमा कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः आवेदन शुल्क कम जमा कये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
DMO-23/2016-17	01,02,03	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : शून्य

व्यय से संबंधित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(1) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा संपादित विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पत्रावली

2. **सतत् अनियमितताएं:**

टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजपाल लेघा	ज्येष्ठ खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला खान अ धकारी रूद्रपुर ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र